DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------दैनिक जागरण नई दिल्ली, 14 जून, 2023---------DATED----------

चार और गांव बनेंगे 'आदर्श'

एलजी ने निजामपुर, जौंती, रावता और देवराला को लिया गोद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: कुतुबगढ़ में मिले सकारात्मक परिणामों से उत्साहित होकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अब चार नए गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए गोद लिया है। ये गांव उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के निजामपुर, जौंती और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में रावता और देवराला हैं। इन चारों गांवों में सभी नागरिक सुविधाओं के लिए बुनियादी संरचनाओं, स्वास्थ्य सुविधाएं, आजीविका के अवसर और व्यापक जल और पौधारोपण प्रबंधन योजनाएं जल्द शुरू की जाएंगी।

वीके सक्सेना

उपराज्यपाल सचिवालय के मुताबिक निजामपुर और जौंती कंझावला में, जबकि रावता और देवराला कापसहेड़ा में स्थित है। इन गांवों को कुतुबगढ़ गांव की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। वर्ष 2011 की जनसंख्या के मुताबिक निजामपुर की आबादी छह से सात हजार, जबकि जौंती की आबादी आठ से नौ हज़ार के बीच है। रावता की आबादी 2933 और देवराला की आबादी 524 है।

आदर्श गांव के तहत किए जा रहे हैं ये काम

- एमसीडी डिस्पेंसरी को पालीक्लीनिक में अपग्रेड किया जा रहा है
- पहली बार स्थानीय सरकारी स्कूल में साइंस स्ट्रीम शुरू की जा रही है।
- गांव में अब तक 544 एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी हैं
- पहली बार गांव में डाकघर बन रहा
- डीडीए गांव में दो तालाब विकसित कर रहा है। दो पार्कों में ओपन जिम के साथ चार नए पार्क बन रहा है।
- 60 स्थानीय किसानों को प्रशिक्षित किया गया है।
- स्थानीय सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए नए बस रूट जोड़े गए हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 14 जून 2023 ATED----------

LG ने चार और गांव गोद लिए, बनाए जाएंगे मॉडल विलेज

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

कुतुबगढ़ गांव को विकसित करने की पहल के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के चार और गांव गोद लिए हैं। इन गांवों को मॉडल गांव बनाया जाएगा। इनमें नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के निजामपुर, जोंटी और रवाटा शामिल हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली का देवराला भी विकसित किया जाएगा।

कुतुबगढ़ गांव की तरह होंगे डिवेलप

इन गांवों में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा, रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। पानी के प्रबंधन, जेंडर के मसले समेत कई और काम किए जाएंगे।

2011 की जनगणना के अनुसार, निजामपुर की जनसंख्या 6000-7000 और जोंटी की 8000-9000 है, जबकि

एलजी ने कुतुबगढ़ को विकसित करने की पहल 2022 में की थी

रवाटा और देवराला की जनसंख्या 2933 और 524 है। एलजी ऑफिस की ओर से बताया गया कि कुतुबगढ़ के मॉडल पर इन चार ग्रामीण गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार के लिए सभी कोशिशें की जाएंगी। कुतुबगढ़ को एक आदर्श गांव के रूप में विकसित करने की पहल सितंबर, 2022 में की थी।

कुतुबगढ़ में एमसीडी डिस्पेंसरी को पॉली क्लीनिक में अपग्रेड किया जा रहा है। पहली बार पोस्ट ऑफिस बनाया जा रहा है। स्थानीय सरकारी स्कूल में साइंस स्ट्रीम शुरू की जा रही है। गांव में अब तक 544 एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी हैं। डीडीए गांव में दो तालाब विकसित कर रहा है। दो पार्कों में ओपन जिम के साथ डीडीए चार नए पार्क विकसित कर रहा है। 60 स्थानीय किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों में कुशल सिंचाई तंत्र और जैविक खेती में प्रशिक्षित किया गया है। जिला प्रशासन युवा आकांक्षा सर्वेक्षण रख रहा है, ताकि स्थानीय युवाओं के लिए करियर की संभावनाओं को देखते हुए आकलन किया जा सके। स्थानीय सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए नए बस रूट जोड़े गए हैं। यही सब कदम बाकी चार गांवों में भी उठाए जाएंगे।

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 14 जून 2023

जनकपुरी : पार्क का गेट जर्जर, हादसे का है डर

■ एनबीटी न्यूज, जनकपुरी:

डी-ब्लॉक में डीडीए के पार्क का गेट जर्जर हालत में है। इसके छज्जे में दरारें आई हुई हैं। यह पार्क सर्वोदय कन्या विद्यालय के गेट नंबर एक और दो के सामने बना है।

छत से प्लास्टर गिर रहा है, सरिए तक दिखने लगे हैं

छत से प्लास्टर उतर गया है और सरिए तक दिखने लगे हैं।

स्थानीय निवासी पार्वती ने बताया कि पार्क का गेट काफी समय से खस्ताहाल है। यहां बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं। गेट के जर्जर होने के कारण हादसे

शिकायत पर भी सुनवाई नहीं

का डर लगा रहता है। स्थानीय निवासी राम आसरे ने बताया कि गेट के साथ की दीवार में भी दरारें आई हुई हैं।

पांडव नगर में अवैध कब्जे का आरोप

■ एनबीटी न्यूज, पांडव नगर: पांडव नगर में पुलिस अपार्टमेंट के सामने मदर डेयरी से लगी हुई डीडीए के जमीन पर अवैध कब्जे होने का आरोप है। लोगों का आरोप है कि सरकारी जमीन अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इस बात की शिकायत डीडीए से भी जा चुकी है।

डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण, शिकायत पर एक्शन नहीं

जय चंद घावरी ने बताया कि पहले भी अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटा दिया गया था। डीडीए के इस खाली पड़े जमीन पर भूमाफिया अपना सामान रखकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की शिकायत वह डीडीए से की जा चुकी है। हालांकि अब तक कार्रवाई नहीं की गई।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAI Hindustan Times NEW DELHI WEDNESDAY JUNE 14, 2023

Delhi govt nod for policy to regulate food trucks in city

HT Correspondent
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Chief minister Arvind Kejriwal on Tuesday approved a policy to regulate the food truck business in Delhi and create food hubs in several areas, a move expected to kickstart a new trend in Delhi which is known for its street food vendors and snacks, government officials aware of the matter said.

The officials added that food trucks will be allowed to operate round-the-clock to facilitate night-time economy in the city.

The policy was first announced in the Delhi government's "Rozgaar Budget" for 2022-23 as part of the measures to provide an impetus to job creation in the Covid-hit economy.

The government has initially identified 16 locations, where multiple food trucks will be allowed to operate, to create food courts. If successful, the model will be replicated across Delhi, the officials added.

The CM said that the policy is expected to generate employment and help the state's economy. "This plan will allow the citizens of Delhi to enjoy delicious meals even late at night. Additionally, it will create opportunities for employment on a large scale and strengthen the economy," Kejriwal said.

According to officials, the first 16 food hubs will come up at August Kranti Marg (near Hudco Place), Near Priya Cinema in Vasant Vihar, DDA Park in Rohini, Mandir Marg in Vasant Kunj, Press Enclave Road in Saket and Delhi's metro's parking lots in Rohini East, Vasant Vihar, Patel Chowk, Vishwavidyalaya, Dwarka Sector 9, Janakpuri East and Netaji Subhash Place among others.

The government has identified 16 locations for these trucks. HT

The government is also talking to other land-owning agencies such as Delhi Transport Corporation and Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) to identify more areas that can be developed as food hubs.

Officials said a private company will be selected to manage the overall operations under the policy, and a "minimum license fee" will be imposed on food truck operators.

Food trucks are common in several cities in Europe, American and Australia, the officials said, adding the policy will regulate the sector which has so far operated in an unorganised manner. They said the policy will encourage entrepreneurs to establish proper food trucks, instead of the current small shops that are shaped like a vehicle. The policy will encourage such businesses to organise and prosper in a legal framework.

Public Works Department (PWD) minister Atishi said that the policy will also ensure "high standards of aesthetics, sanitation and hygiene" at all food destinations. "The policy aims to create a safe and enjoyable dining environment for patrons, prioritising their well-being and satisfaction," she said.

The officials said that the operators will have to register with the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) as a mobile vending unit as well as get no objection certificates (NOCs) from the RTO, Delhi Police, fire department, municipal corporation and shops and establishments department.

Officials said that the draft policy will be finalised by July 31, and is expected to be cleared by the state cabinet by August 31.

Responding to the announcement, Delhi BJP spokesperson Praveen Shankar Kapoor said, "... To bring such a policy is not in the Delhi government domain, it is the work of MCD. Secondly, a concept food truck policy was approved by the MCD administrator in 2022 and is already in place."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 14 जून 2023

नए फ्लैट्स की स्कीमें दो चरणों में की जाएंगी लॉन्च

DDA के 17800 फ्लैट दो साल में होंगे तैयार

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

अगले दो साल में डीडीए के 17829 फ्लैट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। इन फ्लैट्स में एचआईजी, एमआईजी, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स शामिल हैं। सबसे अधिक एमआईजी के फ्लैट्स हैं। डीडीए के वाइस चेयरमैन सुभाशीष पांडा ने बताया कि दो चरणों में यह फ्लैट्स तैयार होंगे और इनके लिए दो हाउसिंग स्कीमें ही लॉन्च की जाएंगी।

इन फ्लैट्स में ज्यादातर एमआईजी के हैं

डीडीए के मुताबिक, अक्टूबर 2023 तक 11,449 फ्लैट्स तैयार हो जाएंगे। इसके बाद 6380 फ्लैट्स मार्च 2024 तक तैयार होंगे। इनमें से ज्यादातर फ्लैट्स का काम लगभग पूरा हो गया है। यह सभी फ्लैट्स द्वारका के सेक्टर 19बी, बक्करवाला, द्वारका सेक्टर-14, नरेला सेक्टर ए-1 से ए-4 में हैं। अधिकारी के अनुसार, एचआईजी फ्लैट्स द्वारका सेक्टर-19 बी में आ रहे हैं। यहां डीडीए पहली बार पेंटहाउस भी लेकर आ रहा है। द्वारका के पेंटहाउस में लोगों को टैरेस गार्डन की सुविधा भी मिलेगी। द्वारका सेक्टर-19 बी में 116 एचआईजी, 14 पेंट हाउस और 328 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। द्वारका के अलावा नरेला में भी एचआईजी फ्लैट्स बन रहे हैं।

डीडीए के फ्लैट्स

कुल	HIG	MIG	LIG	जनता	कुल
कितने बने	-	-	19680	5133	24813
अप्रैल 2020 तक निर्माणाधीन	4063	7687	316	5763	17829
अक्टूबर 2023 तक पूरे होने वाले	2938	2491	316	3904	11449
मार्च 2024 तक पूरे होने वाले	1125	3396	0	1859	6830

डीडीए के मुताबिक इस साल दिवाली पर फ्लैट्स की पहली स्कीम आ सकती है

अधिकारियों के मुताबिक, इन फ्लैट्स की कीमत तय नहीं की गई है। डीडीए के मुताबिक, इस साल दिवाली पर नए फ्लैट्स की पहली स्कीम आ सकती है। इसके लिए अलॉटमेंट का काम अगले साल के पहले तीन महीनों में करने की संभावना है। डीडीए के अनुसार, पेंटहाउस 266 स्क्वायर मीटर, एचआईजी फ्लैट्स का साइज 129 स्क्वायर मीटर और 150 स्क्वायर मीटर में हो सकता है।

वहीं एमआईजी के फ्लैट्स 84 स्क्वायर मीटर और एलआईजी फ्लैट्स का साइज 40 स्क्वायर मीटर है। डीडीए ने अब तक 54 हाउसिंग स्कीम लॉन्च की हैं। इन स्कीमों के तहत 417063 फ्लैट्स उतारे गए हैं।

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, JUNE 14, 2023

16 hubs picked in city to roll out food trucks

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The city will soon have mobile food truck hubs similar to New York and Hong Kong. Chief minister Arvind Kejriwal on Tuesday gave his in-principle approval to the policy.

The plan is to have the hubs in 16 locations. These are Rohini East, Vasant Vihar, Patel Chowk, Vishwavidyalaya, Dwarka Sector 9, Janakpuri East, Netaji Subhash Place, August Kranti Road (near HUDCO Place), near Priya Cinema in Vasant Vihar, DDA Park in Rohini, Mandir Marg in Vasant Kunj, Press Enclave Road in Saket, Pitam Pura Dilli Haat, Janakpuri Dilli Haat, IP Extension and a vacant plot near the DM West office in Rajouri Garden. "Upon successful implementation, the model will be replicated across Delhi," a statement from the chief minister's office said.

Kejriwal took to Twitter to announce the introduction of the policy. "This plan will allow the citizens of Delhi to enjoy delicious meals even late at night. Additionally, it will create opportunities for employment on a large scale and strengthen the economy," he tweeted.

Mobile food trucks have gained popularity in many cities abroad. Following this trend, the government aims to promote the food culture here, the statement said.

The objective is to establish Delhi as the "food truck capital". The government intends to support small businesses, while simultaneously generating jobs and boosting the night economy.

The PWD has identified the locations that include well-known marketplaces. PWD minister Atishi said the policy will generate jobs and contribute to the city's economy.

Delhi BJP spokesperson Praveen Shankar Kapoor said: "First and foremost, to bring such a policy is not in the Delhi government's domain. It is the work of the Municipal Corporation of Delhi."

Second, a concept food truck policy was approved by the MCD administrator in 2022 itself and it is already in place. The moment the MCD's standing committee wants to, it can be implemented, the BJP leader said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- हिन्दुस्तान 14 जून, 2023

निजी प्राइमरी/मिडिल स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में तब्दील की राह आसान

स्कूल अपग्रेड करने के लिए एफएआर शुल्क नहीं लगेगा

राहत

■ प्रभात कुमार

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने कहा है कि सावर्जनिक भूमि पर बने निजी स्कूलों को अपग्रेड करने या सुविधा बढ़ाने के लिए निर्माण करने पर डीडीए अतिरिक्त एफएआर का शुल्क नहीं ले सकती।

न्यायालय ने कहा है कि जब केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर स्कूलों को अतिरिक्त एफएआर के बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है तो डीडीए के पास इस मद में शुल्क वसूलने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। हाईकोर्ट के इस फैसले से राजधानी में निजी प्राइमरी/मिडिल स्कूलों को अपग्रेड करके उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में तब्दील करने की राह आसान हो जाएगी।

जस्टिस नज्मी वजीरी और विकास महाजन की पीठ ने अपने एकल पीठ के फैसले को बहाल रखते हुए डीडीए की अपील को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा है कि तथ्यों से जाहिर है कि सरकार ने वैधानिक अधिसूचना के माध्यम से स्कूलों को मास्टर प्लान-2021 के अनुसार एफएआर में बढ़ोतरी की अनुमति दी है। इसमें स्पष्ट किया है कि इसके लिए अपग्रेडशन शुल्क नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि भूमि पहले से ही आवंटित है और केवल अतिरिक्त एफएआर का इस्तेमाल किया जाना है।

अदालत ने डीडीए की अपील को खारिज किया

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि ये अधिसूचना कोई ऐसी चीज नहीं है, जिससे डीडीए पीछे हट सकता है। इन वैधानिक अधिसूचनाओं को बड़े पैमाने पर जनता की भलाई के लिए उनमें परिकल्पित लाभ का अनुकूलन करने के लिए पूरी तरह से लागू किया जाना है। यह टिप्पणी करते हुए उच्च न्यायालय ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ डीडीए की अपील को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि प्राथमिक विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक में अपग्रेड करना न तो डीडीए के अधिकार क्षेत्र में आता है और न ही इसके दायरे में। यह काम शिक्षा निदेशालय और सीबीएसई का है।

सरकार ने इस बारे में 17 जुलाई 2012 और 24 जनवरी, 2014 को डीडीए अधिनियम की धारा 57 और 58 के तहत अधिसूचना जारी की थी। पीठ ने कहा है कि डीडीए अधिनियम की धारा 57 और 58 के तहत जारी सांविधिक अधिसूचनाएं लीज डीड/विलेखों पर प्रबल होंगी, जो डीड निष्पादित करने के दौरान उस समय के लागू मास्टर प्लान के आधार पर था। पीठ ने कहा है कि हालांकि, अब मास्टर प्लान दिल्ली में स्कूल चलाने के लिए बढ़े हुए एफएआर और भूमि क्षेत्र की कम आवश्यकता की अनुमति देता है और यह एकीकृत स्कूलों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। ऐसे में मास्ट प्लान के वैधानिक प्रभाव के लाभ से स्कूलों/सोसायटियों को वंचित नहीं किया जा सकता है।

डीडीए की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने न्यायालय को बताया कि एकल पीठ का फैसला कई कानूनी खामिया व्याप्त है। उन्होंने न्यायालय ने एकल पीठ के फैसले को रद्द करने और डीडीए को निजी स्कूलों से अतिरिक्त एफएआर इस्तेमाल करने पर इसका शुल्क वसूलने का निर्देश देने की मांग की है। दूसरी तरफ निजी स्कूलों के संघ एक्शन कमेटी ने मास्टर प्लान और केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचनाओं का हवाला देते हुए कहा कि डीडीए को अतिरिक्त एफएआर का शुल्क नहीं वसूल सकती।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com

NAME OF NEWSPAPERS- नई दिल्ली | बुधवार, 14 जून 2023 -DATED-

कवायद

निजामपुर, जौंती, रावता और देवराला में मुहैया कराई जाएंगी इन्फ्रा, स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं

एलजी ने चार गांव लिए गोद, पर्याप्त नागरिक सुविधाएं मिलेंगी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली में सांसदों की तर्ज पर एलजी वीके सक्सेना ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली में निजामपुर, जौंती और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में रावता, देवराला को गोद लिया है, इन्हें मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा।

इससे पहले एलजी ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के कुतुबगढ़ गांव को गोद दिया था, इसे मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके उत्साहजनक परिणामों से उत्साहित एलजी ने चार और गांवों को गोद लेने में दिलचस्पी दिखाई है। इन गांवों को पर्याप्त नागरिक बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया जाएगा।

कुतुबगढ़ गांव के विकास मॉडल को दोहराया जाएगा

सितंबर 2022 में एलजी ने कुतुबगढ़ को गोद लिया था, एलजी की अध्यक्षता में 500 किसानों ने चंदन के 1000 पौधे लगाए थे। बाद में एलजी वीके सक्सेना ने 13 अप्रैल 2023 को एक बार फिर कुतुबगढ़ गांव का दौरा किया और ग्रामीणों को 2000 अमरूद और 1000 अंगूर के पौधे वितरित किए। एलजी ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कुतुबगढ़ को एक मॉडल गांव के रूप में विकसित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि कुतुबगढ़ को पहले मॉडल गांव के रूप में विकसित करने के बाद विकास के उसी मॉडल को अन्य गांवों में दोहराया जाएगा।

चारों गांवों में पहले व्यापक स्तर पर जल प्रबंधन होगा। बड़े पैमाने पर पौधरोपण कर हरियाली बढ़ाई जाएगी। गांव की विरासत को संरक्षित किया जाएगा। इन्फ्रा, स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं विकसित की जाएंगी। वैज्ञानिक तरीके से पशुधन प्रबंधन व विकास के लिए गांव में काम शुरू किया जाएगा और लोकल स्तर पर आजीविका के अवसर पैदा किए जाएंगे। जौंती गांव को इससे पहले पूर्व सांसद उदित राज ने गोद लिया था, लेकिन गांव में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। एलजी कार्यालय के मुताबिक, इन चार गांवों को मॉडल गांव के तौर पर विकसित करने की पहल शुरू की गई है। 2011 की जनगणना के मुताबिक निजामपुर गांव की जनसंख्या करीब 6000-7000 और जौंती की करीब 8000-9000 है, जबकि रावता की जनसंख्या करीब 2933 और देवराला की 524 है। इन चार गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। कृषि, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।

यह मॉडल अपनाया जा रहा

- एमसीडी डिस्पेंसरी को पॉलीक्लीनिक में अपग्रेड किया जाएगा
- गांव में डाकघर बनेगा
- सरकारी स्कूल में साइंस स्ट्रीम होगी
- 544 एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी हैं
- डीडीए दो तालाब विकसित करेगा
- दो पार्कों में ओपन जिम के साथ डीडीए चार नए पार्क विकसित करेगा
- 60 स्थानीय किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) में कुशल सिंचाई तंत्र और जैविक खेती में प्रशिक्षित किया गया है
- आईएंडएफसी विभाग ने कुतुबगढ़ में साइन बोर्ड और गांव के नक्शे लगाए हैं
- युवाओं की आजीविका और कॅरिअर के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू होंगे
- सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए नए बस रूट शुरू होंगे

पंजाब केसरी

इन गांवों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और आर्थिक खुशहाली लाना मुख्य मकसद

एलजी ने गोद लिए चार गांव, सभी बनेंगे मॉडल

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): उत्तर पश्चिम दिल्ली में मॉडल गांव के रूप में विकसित किए जा रहे कुतुबगढ़ गांव के परिणामों से उत्साहित उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चार और गांवों को गोद लेने का फैसला किया है।

ये गांव निजामपुर, जौंती, रावता और देवराला हैं। इन गांवों में उच्च स्तरीय नागरिक अवसंरचना, विरासतों का संरक्षण, आजीविका के अवसर, पशुओं का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन, हेल्थकेयर, उचित तरीके से भूमि का इस्तेमाल, जल प्रबंधन जैसी नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

एलजी सचिवालय के मुताबिक निजामपुर और जौंती उत्तर पश्चिमी दिल्ली के कंझावला में स्थित है जबकि रावता और देवराला दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कापसहेड़ा में स्थित है। इन गांवों को कुतुबगढ़ गांव की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक निजामपुर की आबादी 6 से 7 हजार जबकि जौंती की आबादी 8 से 9 हजार के बीच है। वहीं रावता की आबादी 2933 और देवराला की आबादी 524 है। राजनिवास के अधिकारियों ने कि इन गांवों का विकास कुतुबगढ़ की तर्ज पर किया जा रहा है जिसका मकसद दिल्ली के इन गांवों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और आर्थिक खुशहाली लाना है। जिस तरह से कुतुबढ़ गांव को विकसित किया जा रहा है, उसी तरह से इन गांवों में पानी, कृषि, स्वास्थ्य, जेंडर आदि के मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा। एलजी के सहयोग और उपस्थिति में कुतुबगढ़ गांव को विकसित करने का काम गांव के 500 किसानों द्वारा 1000 चंदन के पौधे लगाए जाने के साथ ही सितंबर 2022 में शुरू हुआ था। इसके बाद 13 अप्रैल 2023 को एक बार उपराज्यपाल ने दोबारा कुतुबगढ़ गांव का दौरा किया और ग्रामीणों को 2000 अमरूद के पौधे और 1000 अंगूर के पौधे लगाने के लिए दिए।

एलजी ने गांव का औचक निरीक्षण करने के दौरान कुतुबगढ़ को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों को समय सीमा के अंदर हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया था। उन्होंने उसी समय कहा था कि जब एक बार कुतुबगढ़ मॉडल गांव के रूप में विकसित हो जाएगा तो इसी तर्ज पर अन्य गांवों को भी विकसित किया जाएगा। कुतुबगढ़ गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का काम प्रगति पर है और इसके तहत निम्नलिखित काम किए जा रहे हैं।

विकसित हो रही ये सेवाएं

- एमसीडी डिस्पेंसरी को पॉलीक्लीनिक में अपग्रेड किया जा रहा है।
- पहली बार गांव में डाक घर बनाया जा रहा है।
- गांव में अब तक 544 एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी।
- डीडीए गांव में 2 तालाब विकसित कर रहा है।
- दो पार्कों में ओपन जिम के साथ डीडीए द्वारा चार नए पार्क विकसित किए जार है।
- 60 स्थानीय किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) में कुशल सिंचाई तंत्र और जैविक खेती में प्रशिक्षित किया गया है।
- आईएंडएफसी विभाग ने कुतुबगढ़ में साइन बोर्ड और गांव के नक्शे लगाए हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPE

the pioneer
NEW DELHI | WEDNESDAY | JUNE 14, 2023

L-G to adopt, develop four more villages

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

With positive results coming after developing Qutabgarh Village in North West Delhi as a model village, Lieutenant Governor VK Saxena has decided to adopt four more villages — Nizampur, Jaunti, Rawta and Deorala. They will have ample civic infrastructure, preservation of heritage, livelihood opportunities, scientific livestock management, healthcare, proper land use and water management among others.

The Raj Niwas said here on Tuesday that Nizampur, Jaunti (in Kanjhawala in North West Delhi) and Rawta, Deorala (in Kapashera in South West Delhi) will be developed on the model of Qutabgarh Village for which the initiatives are under progress.

According to the Census of 2011, Nizampur and Jaunti has population of about 6,000-7,000 and 8,000-9,000 respectively while Rawta and Deoral have 2,933 and 524 people respectively. The Raj Niwas said on the model of Qutabgarh, all efforts will be made for improving the quality of life and economic well-being of people living in these four villages of the national Capital.

Various issues concerning these villages including water issues, agriculture issues, gender issues and health issues besides will be addressed on priority basis like in the Qutabgarh village. Under the aegis of the Lieutenant Governor, initiatives for developing Qutabgarh as a model village was started in September, 2022 with the plantation of 1,000 saplings of sandalwood by 500 farmers.

Later, Saxena once again visited Qutabgarh village on April 13, 2023 and distributed 2,000 guava and grapes saplings (1,000) to the villagers.

During the onsite inspection, Saxena had directed concerned officials to undertake all possible steps to develop Qutabgarh into a model village, while adhering to the stipulated time frame.

He had said once Qutabgarh is developed into the first model village, the same model of development will be replicated in other villages. The initiatives under progress to develop Qutabgarh into a model village included the following and the other four villages will be developed on similar lines.

The steps included up gradation of the MCD dispensary to a poly clinic, a post office is being set up in the village, introduction for the first time of science stream in the local government school, 544 LED street lights have been installed in the village till now.

Moreover, the DDA is developing two ponds in the village. Also, the DDA is developing four new parks with open gym in two parks. Sixty local farmers have been trained at Krishi Vigyan Kendras (KVKs) in efficient irrigation mechanism and organic farming.

The Irrigation and Flood Control Department has installed sign boards and village maps in Qutabgarh. District Administration has conducted Youth Aspiration Survey, so as to assess the skill requirement and other vocational guidance required by the local youths for their livelihood and career prospects. New Bus routes have been added to strengthen local public transport.